SHRI SATYASADHAN CHARKRABORTY: When I said that the steel production was going down, you denied it. Then you also stuck to your own point. Then I referred to the mid-term appraisal of the Planning Commission. My source of information is your document, mid-term appraisal of the Planning Commission. There they have expressed their concern for the production of textile and steel; and that has gone down what was targetted in the 6th Plan. Will you please find out the truth and let me know tomorrow?

SHRI NARAYAN DUTT TIWARI: As far as my knowledge goes, mid-term appraisal has not yet been completely made out ; we have not yet received any midterm appraisal report.

PATRONISING OF PRIVATE DEALERS BY HMT FOR SALE OF WATCHES

154. SHRI B.D. SINGH : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

- (a) Whether it is a fact that Hindustan Machine Tools Ltd. is patronising the private dealers for sale of watches thereby hitting the National Cooperative Consumers Federation which looks after interests of poor consumers;
- (b) whether private by manipulating the prices are able to dispose of their stocks of HMT watches where as NCCF confornted with the task of disposing of unpopular varieties of watches cannot resort to such practices; and
- (c) If so, the remedial measures taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI VIRBHADRA SINGH) : (a) No. Sir.

Oral Answers

(b) and (c). The vailing sales tax structure varies from State to State, both in regard to rate and collection point. In some States sales tax is collected at the first point of sale, while in others, it is levied at the last point of sale. This may enable certain dealers to manipulate prices of watches. HMT has already taken up the matter with the State authorities concerned.

श्री बी । डी । सिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, एक भ्रोर सरकार सहकारिता को बढावा देने की बात करती है ग्रीर दूसरी ग्रीर सरकारी संस्थानों के साथ स्टैप-मदरली ट्रीटमेंट होता है । सवाल यह किया था कि एच० एम० टी० की घड़ियों के संबंध में प्राइवेट डीलर्स को वरीयता दी जा रही है । इसमें इन्होंने इन्कार नहीं किया है। एच एम वी द्वारा करीब 30 घड़ियां विभिन्न प्रकार की बनाई जाती हैं। उनमें क्या माननीय मंत्री जी एक विवरण सभा-पटल पर/ रखने की कृपा करेंगे, जिसमें यह बताया गया हो कि कौन सी घड़ियां ज्यादा पोपूलर हैं श्रीर कौन सी घड़ियां कम पोपूलर हैं स्रीर नेशनल को-ग्रापरेटिव कन्ज्यमर फैडरेशन को कौन कौन सो घडियां एलाट की जाती हैं और प्राइवेट डीलर्स को कौन सी घडियां एलाट की जाती हैं ?

उद्योग तथा इस्पात ग्रौर खान मंत्रो (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मैं माननीय सदस्य को आश्वरत कर्गा चाहंगा कि ऐसा कोई भी विचार एच एम टो । का नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई सहकारी संस्था, विशेष रूप से राष्ट्रीय संस्था है, किसी भी प्रकार का कोई निषेधात्मक दृष्टिकोण ग्रपनाया जाए । इस प्रकार ग्रभिप्राय कभी भी एच एम टी का नहीं हो सकता है। न है ग्रौर न रहेगा । प्रश्न यह है कि क्या व्यापारिक दृष्टिकोण कार्माशयल के **ब्राधार पर होना चाहिए या नहीं ।** म्रापस में इनका जो म्रनुबंध हुम्रा, उसको बार-बार सहकारी संस्थान ने नहीं माना ग्रीर उल्लंघन हग्रा तब व्यापारिक कारणों से एच० एम० टी > को कुछ कार्यवाही करनी पड़ी । जहां तक यह प्रश्न है कि ग्रन्तूबर, 1981 के पहले एच । एम । टी । इस फेडरेशन को ही नहीं, सहकारी संस्थायों को भी सीधे घड़ियां दिया करती थी । लेकिन संस्थान ने कहा कि सारी घड़ियां हमको सीधे दी जाएं तो अन्तूबर 1981 से यह निर्णय लिया गया कि इनको ही दी जाएंगी । यह तो इनके लिए ग्रच्छा किया गया । इसलिए इस संस्थान को शिकायत नहीं होनी चाहिए । माननीय सदस्य से भी मेरा अनुरोध है कि वे अपने प्रभाव का प्रयोग करें ताकि जो अनुबन्ध हैं, उनके ग्रनुसार चला जा सके।

इसके म्रलावा सदन के पटल पर सूचना रखने के बारे में कहा गया है कि 30 प्रकार की घड़ियों में कितनी उनको दी जाती हैं। श्रीमन्, नियम एक जैसे हैं। किसी के लिए नियम म्रलग नहीं हो सकते। लेकिन यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसका विवरण दिया जाए तो मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से बता दूंगा।

श्री बी बी बी सिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, नेशनल को आपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन श्रीर एम एच टी के बीच ऐसा समझौता हुआ था कि इनको 7 प्रतिशत डिसकाउंट दिया जाएगा, लेकिन वह डिसकाउंट घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया, जबिक प्राइवेट डीलर्स को डिसकाउंट 6 प्रतिशत देते हैं । इस एनामली को दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है ?

श्री नारायण इस तिवारी: ग्रध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि आपस में अनुबंध हुआ, लेकि। सम्माननीय सदस्य देखेंगे कि/ फेडरेशन को बहुत सी सहूलियतें दी गईं । पहले सात परसेंट डिस्काउंट दिया गया ग्रीर 30 हजार घडियां प्रति माह बेचने का इन्होंने वादा किया । बाद में इन्होंने कहा कि 20 हजार करिए, वह भी मान लिया गया। किर 16 हजार प्रति माह कर दिया गया । व्यापारियों के लिए 4 प्रतिशत पहले है ग्रौर तीन प्रतिशत बिलिंग के समय है, इन्होंने कहा कि हमको पहले ही दीजिए, इनकी वह बात भी मानी गई । इसके बावजुद इस संस्थान ने ग्राधी घड़ियां भी नहीं बेचीं ...।

MR. SPEAKER: Do you mean to say that you pampered them?

श्री नारायण दत्त सिशारी : पेंपर तो नहीं कह सकते, हां हमने सहकारी ग्रांदोलन को बल देने की चेष्टा की है। ग्रांदोलन को बल देने की चेष्टा की है। ग्रांदोलन को इसमें नहीं है। ग्रांदोलन सदस्य को यह शिकायत है कि घाटा क्यों हो रहा है, कर्माश्यल रोल का परिपालन क्यों नहीं कर रहे हैं। दो लाख रुपए की जमानत दी थी, उसमें से रुपया काटा है। रुपया नहीं दिया गया, इसलिए काटा है। कोई एनामली नहीं है। मैं एच० एम० टी० से कहूंगा कि दुवारा इस फेडरेशन से बात करे। फेडरेशन भी ग्रांपनी सेल बढ़ाए ग्रीर

एक इस टी० के एग्रीमेंट को कायम

MR. SPEAKER: Shri Narain Choubey. Absent.

Shri Subhash Chandra Bose Alluri. Absent.

K.M. Madhukar. Absent. Shri

Patil. Shri Balasaheb Vikhe

AN HON. MEMBER: So many absentees.

MR. SPEAKER: After a week, my Members go for rest.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Everybody has got dengue fever.

Second Indian Expedition Antarctica

*160. SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL:

SHRI SUBHASH YADAV:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

- (a) whether it is a fact arrangments for the second Indian expedition to Antarctica have been completed ;
- (b) if so, what would be the team and the objectives set out for this expedition;
- (c) whether Government have any research vessel made indigenously; and
- (d) if not, whether there is any proposal to manufacture such ships vessels so that the country's dependence on the foreign countries is eliminated?

THE MINISTER OF STATE INTHE DEPARTMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY, ELECTRONICS, OCEAN DEVE-LOPMENT AND THE DEPART-MENT OF NON-CONVENTION-AL ENERGY SOURCES IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI C.P.N. SINGH):(a) Yes, Sir.

- (b) The team will consist of about 26 members including sci entists, engineers, technicians, pilots, doctors and a photographer. The objectives of the expedition are to conduct scientific investigations on the continent of Antarctica, and carry out surveys for identifying a suitable site for setting up a permanent research station on Antarctica.
- (c) Government do not have any research vessel capable of navigation in polar conditions.
- (d) The possibility of manufacturing ships capable of navigation in polar conditions is being explored.

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: Has the Government appointed any task force? If so, what are its terms of reference? When is the report of this Task Force likely to be submitted? Is the Government of India taking assistance from foreign countries in the matter of technical knowhow and also vessels to carry out our mission in Antarctica If so, which are the countries, which have agreed to extend such help and details thereof?

SHRI C.P.N. SINGH: Regarding the first part of the question, the Task Force has merely been set up to explore the feasibility of being either to manufacture or have a ship manufactured from out side which would be an ice-breaker. Committee is still deliberating and we have not got the final report. However, that will not hold up our second expedition, which is scheduled to take place by the end of Novembe.

Regarding the Foreign assistance, most of the equipment that had gone on board, was indigenous. But the vessel was foreign and was chartered. Even this time, it is a chartered foreign vessel. But 80 percent of the communication and navigation equipment is indigenous. Only 20 per cent is to be imported. So, the